हिन्दी दैनिक

स्वाभिमान जागरण

RNI.No.- UPHIN/2021/84176

लखनऊ से प्रकाशित..

वर्ष : 04 अंक : 332 लखनऊ, बुधवार 28 अक्टूबर 2026 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1.00 रूपया

संक्षिप्त खबरें

पूर्व विधायक और वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन, अधिवक्ताओं ने कार्य स्थगित कर जताया शोक

एजेंसी

बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व विधायक आरके दास गुप्ता का मंगलवार को सुबह हृदयाघात से निधन हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह अचानक अस्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुप्ता पांच दशक से अधिक समय तक वकालत करते रहे। वह बीकानेर बार संघ के अध्यक्ष पद पर आठ बार चुने गये। वकालत के अलावा वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। आपातकाल में वह जेल भी गये और 18 महीने जेल में रहे। इसके वह वर्ष 1977 में जनता पार्टी की ओर से श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गये। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और कभी समझौता नहीं किया। इसके चलते सरकार की नीतियों से असहमत होने पर उन्होंने डेढ़ वर्ष बाद ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया।

दिवाली से पहले खरीदारों की मौज, सोना-चांदी हुआ और सस्ता

एजेंसी

नयी दिल्ली। धनतेरस और दिवाली से पहले सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से जारी गिरावट के बीच मंगलवार को भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा। घरेलू बाजार एमसीएक्स पर सोने में 0.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, और यह 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। वहीं चांदी 2.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1.91 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई। इस तरह, सोने और चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तरों से काफी नीचे आ चुकी हैं, जिससे त्योहारी खरीदारी की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। बाजार जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरों की आशंका, कमजोर निवेश मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी बिकवाली का असर घरेलू कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है।

एलपीजी की कमी की अफवाहों से बढ़ी सिलेंडर बुकिंग

एजेंसी

पणजी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ आयात के स्रोतों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 की। उन्होंने यह भी कहा कि देश की तेल शोधन क्षमता 2030 तक बढ़कर 30 करोड़ टन सालाना होने की उम्मीद है। पुरी ने यहां आयोजित २९वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन के दौरान अलग से संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दैनिक घरेलू एलपीजी उत्पादन 34,000 टन से बढ़कर 55,000 टन हो गया। इसके साथ ही अमेरिका और अल्जीरिया जैसे देशों से आयात बढ़ाकर खाड़ी क्षेत्र से आपूर्ति में आए गतिरोध की भी भरपाई की गई। उन्होंने कहा कि संकट की प्रकृति का पहले से अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उससे निपटने की तैयारी पहले से की जा सकती है।

प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही युवाशक्ति

मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति की नई पहचान भी बताई

एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही है। उन्होंने वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार की बदली कार्य संस्कृति से भी प्रदेशवासियों को अवगत कराया और रोजगार सृजन में युवाशक्ति की नई पहचान भी बताई। मुख्यमंत्री ने लिखा कि नवाचार की नई सोच हो, उद्यमिता का साहस हो या विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही है। इसी ऊर्जावान युवाशक्ति के सामर्थ्य, सृजनशीलता और उपलब्धियों का अभिनंदन करने के लिए आज



लखनऊ में आयोजित टीओआई यूथ आइकॉन्स समिट एवं अवार्ड्स 2026 में सहभागिता करूंगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को अवसरों के अभाव में पलायन करना पड़ता था। भर्तियों में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और अव्यवस्था से युवाओं का भविष्य अंधकारमय था। प्रतिभा थी, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए अपेक्षित अवसर और प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद डबल इंजन सरकार ने इस कार्य-संस्कृति को बदला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने पारदर्शी भर्ती, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए आगे बढ़ने के नए अवसर सृजित किए हैं। आज उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति केवल रोजगार की आकांक्षी नहीं, बल्कि रोजगार सृजन में भी अपनी नई पहचान गढ़ते हुए श्विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारतश के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

असत्य के खिलाफ सच्चे योद्धा की तरह डटे रहे राहुल, अदालत के फैसले पर बोलीं प्रियंका

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में राहुल गांधी को बरी किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि उनके भाई जिस तरह असत्य के हमले के खिलाफ डटे रहे, उसके लिए अपार साहस, दृढ़ता और एक सच्चे योद्धा जैसी लगन की जरूरत होती है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की एक्स पर की गई उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही, जिसमें उन्होंने सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में बरी कर दिया था।

कोई इसका अनादर ना करे... वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने की मांग, एससी ने केंद्र को जारी किया नोटिस

एजेंसी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को दिल्ली हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और इस मामले को ऐसी ही अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया। अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से दाखिल इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि चूंकि इसी तरह की एक रिट याचिका पहले से ही शीर्ष अदालत में लंबित है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित इस जनहित याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। याचिका में कहा गया, वंदे मातरम् हमारे इतिहास,



संप्रभुता, एकता और गौरव का प्रतीक है। यदि कोई नागरिक किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य से इसका अनादर करता है, तो यह न केवल एक असामाजिक कृत्य होगा, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारे सभी अधिकारों और हमारे अस्तित्व के लिए भी विनाशकारी होगा। याचिका में कहा गया, इसलिए, प्रत्येक नागरिक को न केवल ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए, बल्कि यदि कोई उपद्रवी वंदे मातरम् का अनादर करे, तो उसे रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए।

मोदी विरोध में कांग्रेस सोचने, समझने, सुनने की क्षमता खो चुकी है : शिवराज सिंह चौहान

एजेंसी

भोपाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध में विपक्षी पार्टी इतनी श्अंधीश हो गई है कि उसने सोचने, समझने और सुनने की क्षमता खो दी है। चौहान ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उसका मौजूदा व्यवहार एवं भाषा उसके पतन की पराकाष्ठा है। केंद्रीय कृषि मंत्री की यह टिप्पणी मतदाता सूचियों के



विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वापस लेने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच आई है। चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध में कांग्रेस इतनी अंधी हो गई है कि उसने सोचने, समझने और सुनने की क्षमता खो दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, वह उसके पतन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आगामी त्योहारों के दौरान कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे पर निशाना साधते हुए चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा रही है और आम नागरिकों तथा व्यापारियों की चिंताओं की अनदेखी कर रही है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) ने एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने की घोषणा की है। व्यापारियों ने विपक्षी गठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस से रैली 10 नवंबर के बाद आयोजित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि दिवाली के बाद तक रैली टालने से साल के सबसे व्यस्त कारोबारी दौर में व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

गैरसैंण में विधानसभा घेराव के दौरान हंगामा, कांग्रेस और उक्रांद कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत

एजेंसी

गैरसैंण। उत्तराखंड के चमोली जिले के भरारिसैन में विधानसभा स्थल की ओर विरोध मार्च के दौरान गैरसैंण के पास सिमली मोड़ पर एक बैरिकेड पर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, कागजी रिसाव, महिला सुरक्षा और गैरसैंण को स्थायी राज्य राजधानी बनाने सहित 14 जनहित के मुद्दों पर सत्तारूढ़ भाजपा राज्य सरकार को निशाना बनाया। कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) और स्वराज पार्टी के आह्वान पर मंगलवार को राज्य विधानसभा का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में लगाए गए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी जमकर धक्का-मुक्की और झड़प हुई। विपक्षी दलों की ओर से प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित विधानसभा परिसर के प्रस्तावित घेराव को रोकने के लिए पुलिस ने वहां जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए थे, जिसके कारण इन रास्तों पर भारी यातायात जाम लग गया। जंगलचट्टी में बैरिकेड तोड़ने की



कोशिश करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की जनविरोधी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड में श्वीआईपीश की कथित संलिप्तता की जांच सहित कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के घेराव का आह्वान किया था। विधानसभा पहुंचने के रास्ते में जंगलचट्टी और दिवालीगांव में बैरिकेड लगाए जाने के कारण गैरसैंण-कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह 10 बजे से पूरी तरह बंद रहा। कांग्रेस, उक्रांद और स्वराज पार्टी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की।

दिवाली पर पटाखों के शोर और प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार के कदमों पर जताई संतुष्टि

एजेंसी

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले शोर और वायु प्रदूषण को लेकर दायर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पहले के आदेशों के पालन में देरी हुई, लेकिन अब



प्रशासन ने तेजी दिखाई है। जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ ने 26 अक्टूबर के आदेश में यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) की ओर से हलफनामा दाखिल कर प्रदूषण और शोर पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। बीएमसी ने कोर्ट को बताया कि पर्यावरण विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर अजय राणे को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। 22 अक्टूबर को श्लोकसत्ताश और श्इंडियन एक्सप्रेसश में जन-जागरूकता संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जबकि 25 अक्टूबर से टीवी विज्ञापनों का प्रसारण शुरू किया गया है। बीएमसी के अनुसार, रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, हाईवे और बीएमसी के पोर्टल पर भी जागरूकता के लिए होर्डिंग और डिस्प्ले लगाए गए हैं। स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। बीएमसी ने बताया कि शोर से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 पर शिकायतें ली जा रही हैं। इन शिकायतों को सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को भेजा जाएगा। वहीं, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के तहत दीपावली 2026 के दौरान हवा और शोर के स्तर की विशेष निगरानी की जाएगी। इसके लिए संबंधित प्रोटोकॉल और मैनुअल तैयार किया गया है। पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने कोर्ट को बताया कि सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को हाईकोर्ट के आदेशों की जानकारी दे दी गई है। बिना लाइसेंस वाले लाउडस्पीकर और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुंबई की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी झुग्गी-बस्तियों में रहती है। ऐसे में इन इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए नगरसेवकों और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) के सीईओ को शामिल करते हुए बैठक की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि झुग्गी-बस्तियों के प्रभावशाली लोगों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। सेलिब्रिटी को इस अभियान से जोड़ने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकारी खजाने से पैसे नहीं दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि फिल्मी सितारे और खिलाड़ी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वेच्छा से आगे आएंगे। कोर्ट ने फिलहाल प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों पर संतोष जताया और मामले को आगे की निगरानी के लिए सूचीबद्ध रखा।

पत्रकार से धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर 3 नवंबर को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

एजेंसी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 3 नवंबर को एक गर्भवती महिला पत्रकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला इंडिया ब्लॉक के नेताओं के वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट परिसर तक निकाले गए मार्च के दौरान का है। मामले का जिक्र वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के सामने किया। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकार से जुड़ी याचिका अभी तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है। गौरव भाटिया के जवाब में सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और इस पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। पत्रकार रिचा पराशर ने आरोप लगाया था कि जब वह विपक्षी नेताओं के मार्च को कवर कर रही थीं, तो राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा और आक्रामक तरीके से खींचा, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया और वह गिर गईं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीन महीने की गर्भवती रिचा पराशर



ने आरोप लगाया कि यह घटना 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अफरा-तफरी के बीच हुई। कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। वहीं पार्टी नेताओं और समर्थकों ने घटना के वीडियो प्रसारित किए हैं और सवाल उठाया है कि क्या वीडियो से यह साबित होता है कि राहुल गांधी ने पत्रकार को धक्का दिया। यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत परिसर में और उसके आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग वाली एक अलग याचिका की पृष्ठभूमि में आया है। 15 अक्टूबर को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया था और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

राम के नाम पर आए चढ़ावे का हिसाब दो, राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चढ़ावे और कीमती दान में कथित अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि पूरा देश जवाब मांग रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह मांग फिर उठाई कि पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़िए। देश जानना चाहता है कि चंदा चोर कौन हैं? भागीदार कौन-कौन हैं? उच्चतम न्यायालय की देखरेख में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं? उन्होंने दावा किया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के कुछ महीने बाद नवंबर, 2020 में एक निजी ऑडिट कंपनी ने उसके इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कई गंभीर खामियां बताई थीं। रमेश के



मुताबिक, कंपनी ने प्रबंधन को बहुत ही गैरपेशेवर बताते हुए कहा था कि जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय नहीं हैं, दान का व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं है और लेन-देन तथा डेटा एंट्री की दूसरी या तीसरी जांच की व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऑडिट कंपनी ने बैंक मिलान एवं लेखांकन के लिए योग्य कर्मचारियों की कमी और आईटी डेटा की सुरक्षा तथा सत्यापन की उचित व्यवस्था नहीं होने की ओर भी ध्यान दिलाया था। कांग्रेस नेता ने कहा, जब खतरा 2020 में ही लिखकर बता दिया गया था, तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? शिकायत करने वाले को ही क्यों हटाया गया? श्रद्धालुओं के कीमती दान की रसीद तक क्यों नहीं काटी गई? उन्होंने दावा किया कि 2026 में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी पाया कि नकदी की गिनती वाले कमरे से 105 बार नकदी निकाली गई और कर्मचारी कथित तौर पर कैमरों के सामने खड़े होकर उन्हें ढक देते थे। रमेश ने मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय को ठेकों में कथित तौर पर 40 प्रतिशत कमीशन, फर्जी मजदूर दिखाने और सामान के बढ़े हुए बिल बनाने की शिकायत की थी। कांग्रेस नेता के मुताबिक, वर्मा का आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि जांच में कई ऐसी बेशकीमती वस्तुएं मिलीं, जिनके लिए दानदाताओं को रसीद जारी नहीं की गई थी।

सम्पादकीय

वैश्विक राजनीति में बड़े उलटफेर

वैश्विक राजनीति में दो ऐसे बड़े उलटफेर हुए हैं, जो सत्ता को अपनी तिजोरी में रखी संपत्ति समझने वाले नेताओं के लिए बड़ा सबक हैं। पहली घटना दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की है, जहां वर्कर्स पार्टी के नेता लूला डि सिल्वा ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। दूसरी घटना सर्बिया की है, जहां राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी (एसएनएस) को स्टूडेंट लिस्ट ने हरा दिया है। इन दोनों देशों के इस राजनैतिक घटनाक्रम को अमेरिका के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की दखलंदाजी की परंपरा को बरकरार रखते हुए अपनी पसंद की सरकारें यहां बनवाना चाहते थे। ब्राजील में लूला डि सिल्वा की जीत न केवल राजनैतिक बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अहम है। यहां दक्षिणपंथी शासन में बड़ी तेजी से अमेजन के जंगलों का सफाया किया गया, लेकिन लूला के सत्ता में रहने से उम्मीद बंधी है कि अमेजन के जंगल कम से कम अब कुछ और वक्त तक बचे रहेंगे। क्योंकि उद्योगपतियों की गिद्ध दृष्टि यहां लगातार बनी हुई है। वैसे लूला डि सिल्वा ने अपने दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी और लिबरल पार्टी के नेता फ्लावियो बोल्सोनारो को मामूली अंतर से हराया है। लूला को 51.76 प्रतिशत वोट मिले, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो को 48.24 प्रतिशत वोट मिले। बोल्सोनारो के वक्त ही बड़ी तेजी से अमेजन के जंगल काट दिए गए थे और जंगलों में आग लगने की भी कई घटनाएं हुईं। लूला की जीत कई चुनावी सर्वे के अनुमानों के उलट रही, क्योंकि तमाम सर्वे बोल्सोनारो को बढ़त दे रहे थे। अक्टूबर के शुरु में पहले दौर के मतदान में फ्लावियो बोल्सोनारो ने लगभग दो प्रतिशत अंकों की बढ़त हासिल की थी। लेकिन फिर दूसरे दौर में लूला ने उन्हें मात दे दी। यह परिणाम भी संभव नहीं होते, अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मतदान केंद्रों के बंद होने का निर्धारित समय करीब आने पर मतदान की अवधि दो घंटे बढ़ाने का आदेश न दिया होता। ब्राजील के कई नागरिक मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं और लूला के संगठन ने शिकायत की थी कि बहुत सी जगहों पर सार्वजनिक परिवहन में व्यवधान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और ऐसा फैसला दिया, जिससे जनता की जीत हुई। हालांकि हार के बाद फ्लावियो बोल्सोनारो ने नतीजों को मानने से मना कर दिया है, ठीक ऐसे ही 2022 में जाएर बोल्सोनारो ने भी चुनाव में अपनी हार स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। और यही काम ट्रंप ने जो बाइडेन की जीत के बाद किया था। हालांकि एक ही पैंतरा बार-बार काम नहीं करता। लिहाजा तय है कि अब ब्राजील में वामपंथी नेता का शासन रहेगा। लूला इससे पहले 2003 से 2010 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं, फिर चार साल पहले उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति पद हासिल किया था और अब चौथे कार्यकाल के लिए जनादेश उन्होंने हासिल कर लिया है। हालांकि इस बार का कार्यकाल पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी देशों में ट्रंप अपनी पिट्ठू सरकारें बनवाना चाहते हैं। वेनेजुएला में जिस तरह निकोलस मादुरो को अगवा कर ट्रंप ने अपनी मर्जी की सरकार बनाई है, यह दुनिया देख रही है। ट्रंप ने फ्लावियो बोल्सोनारो का सीधे तौर पर समर्थन नहीं किया था, लेकिन कोलंबिया और होंडुरास में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले दक्षिणपंथी उम्मीदवारों का समर्थन किया था। इधर फ्लावियो बोल्सोनारो ने तो पहले ही ब्राजील को अमेरिका के और करीब लाने का वादा किया था। जबकि लूला ने अमेरिका को चुनाव में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि ब्राजील कभी भी किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। लूला के ऐसे ही तेवर ट्रंप को चुभते हैं। पिछले साल से अमेरिका ने ब्राजील पर व्यापार शुल्क और अन्य प्रतिबंध लगाए हैं ताकि लूला डि सिल्वा को सरकार चलाने में दिक्कत आए। लेकिन लूला अमेरिका के आगे नहीं झुके। ब्राजील तेल के समृद्ध भंडार वाला देश है और यहां रेयर अर्थ मिनरल्स का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। इसलिए जाहिर तौर पर ट्रंप की दिलचस्पी इसी में थी कि ब्राजील में भी अमेरिका की जी हुजूरी करने वाली सरकार बने। इधर सर्बिया में भी जनता की ताकत देखने मिली। करीब दो साल से भ्रष्टाचार और सरकार की जवाबदेही के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन वाली श्स्टूडेंट लिस्ट्य ने संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। देश के लंबे समय से प्रभावशाली नेता अलेक्जेंडर वुसिक ने चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। गौरतलब है कि सर्बिया में नवंबर 2024 में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब उत्तरी शहर नोवी साद के रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर बना कांक्रीट का छज्जा ढह गया था, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे ने सरकारी जवाबदेही, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों को लेकर जनता में आक्रोश पैदा कर दिया था। छात्रों ने हादसे की जिम्मेदारी तय करने, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी और फिर विश्वविद्यालयों से शुरू हुआ आंदोलन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में बदल गया। छात्रों के अलावा आम नागरिकों और सरकार के आलोचकों ने भी आंदोलनों में हिस्सा लिया। वुसिक सरकार पर जवाबदेही से बचने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगते रहे, जिसे वुसिक और उनकी पार्टी ने खारिज किया। जनता की नाराजगी की उपेक्षा करने का परिणाम अब अलेक्जेंडर वुसिक को मिल गया है। अब इजरायल में 27 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद पहला आम चुनाव है और इस बार बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता दांव पर है। जनमत उनके विरोध में बताया जा रहा है, क्योंकि पहले गजा फिर ईरान और सीरिया पर थोपे जा रहे युद्धों से लोग त्रस्त आ चुके हैं। ट्रंप तो खुलकर नेतन्याहू को जिताने की अपील कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या यहां भी ब्राजील जैसा हाल होता है, या फिर युद्धपिपासुओं की जीत होती है।

इजरायल का चुनाव : सत्ता कगार पर

असद मिर्जा

इजरायल में 27 अक्टूबर का मतदान तीन साल के युद्ध के बाद नेतृत्व पर जनमत-संग्रह है, लेकिन इसके नतीजे मतपत्र से कहीं आगे तक जाते हैंरू गाजा के भविष्य से लेकर ईरान, वाशिंगटन और क्षेत्रीय स्थिरता तक। बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक ताकत एक सशक्त तर्क पर टिकी है : इजरायल अस्तित्व के खतरों का सामना कर रहा है और केवल उनके पास इनसे निपटने का अनुभव और संकल्प है। वे गाजा, लेबनान और ईरान से जुड़े युद्धों को इस बात का सबूत बताते हैं कि उनकी सरकार ने इजरायल के विरोधियों को कमजोर किया है। जिन मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा है, उनके लिए यह रिकॉर्ड 7 अक्टूबर 2023 की सुरक्षा विफलता पर गुस्से से भारी पड़ सकता है। फिर भी वही हमला उनकी सबसे गंभीर कमजोरी है। उसने उनके कार्यकाल में एक भयावह विफलता उजागर की, और उन्होंने राजकीय जांच आयोग की मांगों का विरोध किया है। उनके विरोधियों का कहना है कि जवाबदेही को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता, और प्रधानमंत्री के निजी तथा राजनीतिक हितों ने युद्ध संबंधी फैसलों को विकृत किया है। अंतिम सर्वेक्षण स्पष्ट जनादेश नहीं, बल्कि कड़े मुकाबले का संकेत देते हैं। गादी आइजनकोट की पार्टी यशर कई सर्वेक्षणों में लिकुड से आगे रही है, पर न विपक्ष और न नेतन्याहू का गुट सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों के करीब दिखता है। इजरायल की आनुपातिक प्रणाली नतीजे को गठबंधन की पहेली बना देती हैरू 3.25 प्रतिशत की चुनावी सीमा के आसपास मंडराती छोटी पार्टियां तय कर सकती हैं कि किस गुट को बेहतर मौका मिलेगा। विपक्ष की नाममात्र की बढ़त भी सत्ता में बदले, यह जरूरी नहीं। नेतन्याहू का भरोसेमंद दक्षिणपंथी आधार कायम है, जबकि 7 अक्टूबर से उग्र हुए कुछ मतदाता विपक्ष की ओर जाने के बजाय और दाईं ओर जा सकते हैं। उनके अभियान का संदेश श्आत्मसमर्पण नहींय जनता के असली डर को संबोधित करता है और उन मतदाताओं को आकर्षित करता है जो मानते हैं कि सैन्य दबाव ही वह एकमात्र भाषा है जिसे इजरायल के दुश्मन समझते हैं। विपक्ष की ऊर्जा किसी एक नीतिगत घोषणापत्र से नहीं, बल्कि शिकायतों के संगम से आती है। प्रदर्शनकारियों ने 7 अक्टूबर की जांच की मांग की, युद्ध के संचालन की आलोचना की, और उन बातों का विरोध किया जिन्हें वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा मानते हैं, जिनमें न्यायिक शक्ति घटाने की कोशिशें शामिल हैं। अति-रूढ़िवादी पुरुषों को सैन्य भर्ती से छूट एक और विवाद हैरू कई इजरायली इस बात से नाराज हैं कि सैन्य और आर्थिक बोझ बराबर नहीं बंटता। आइजनकोट ने भर्ती पर अदालती फैसले लागू करने और जांच कराने का वादा किया है, जिससे असंतोष को सैन्य साख वाला उम्मीदवार मिला है। आइजनकोट की निजी छवि मायने रखती है। पूर्व सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने खुद को संयमित, अपेक्षाकृत सादे विकल्प के रूप में पेश किया है, जो सुरक्षा को समझता है पर नेतन्याहू की राजनीतिक शैली से जुड़ा नहीं है। गाजा युद्ध में उनके परिवार की क्षति उन मतदाताओं के लिए उनकी विश्वसनीयता और गहरी करती है जो खतरों से अनजान कहलाए बिना नई दिशा चाहते हैं। लेकिन बदलाव एक तय कार्यक्रम से ज्यादा व्यापक नारा है। विपक्ष ने उत्तराधिकारी पर सहमति नहीं बनाई है, और उसकी पार्टियां इस पर असहमत हैं कि अरब दलों के साथ सहयोग किया जाए या नहीं, जिनका समर्थन बहुमत के लिए निर्णायक हो सकता है। न ही जीत से फिलिस्तीनियों के मामले में तीखे बदलाव का वादा मिलता हैरू प्रमुख यहूदी विपक्षी नेता पूर्ण फिलिस्तीनी राज्य को खारिज करते हैं, और आइजनकोट ने भविष्य की व्यवस्था को इजरायली सुरक्षा नियंत्रण के तहत स्वायत्तता बताया है। यह गुट देश की मंजिल पर एकमत होने से ज्यादा नेतन्याहू के विरुद्ध एकजुट है। गाजा के फिलिस्तीनियों के लिए चुनाव अहम है, लेकिन केवल सरकार बदलने से जल्द राहत की उम्मीद कम है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को नकारा है और युद्ध को हमास को हराने के लिए जरूरी बताया है। उधर आइजनकोट ने कहा है कि हमास का शासन 18 महीनों में खत्म होना चाहिए, अमेरिकी नेतृत्व वाली योजना या सैन्य साधनों से। दोनों खेमे तरीके और राजनीतिक लहजे में अलग हैं, पर किसी ने फिलिस्तीनी संप्रभुता का स्पष्ट रास्ता नहीं दिखाया। नेतन्याहू की जीत शायद दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों का प्रभाव बढ़ाएगी, जो निरंतर सैन्य नियंत्रण और बस्तियों के विस्तार के पक्षधर हैं। इससे वार्ताधारित राजनीतिक समाधान की गुंजाइश घट सकती है और फिलिस्तीनियों में और विस्थापन तथा बेदखली का डर गहरा सकता है। विपक्ष की जीत पश्चिमी तट में बसने वालों की हिंसा पर अधिक संयम और क्षेत्रीय पहलों के प्रति अधिक कूटनीतिक रुख ला सकती है पर गाजा की पीड़ा अपने आप उस सरकार की प्राथमिकता नहीं बनेगी जिसके मतदाता मुख्यतरू सुरक्षा को, फिलिस्तीनी राज्य को नहीं, केंद्रीय प्रश्न मानते हैं। ईरान सचमुच एक रणनीतिक चिंता भी है और शक्तिशाली चुनावी मुद्दा भी। नेतन्याहू ने मतदान के आसपास ईरानी या उसके सहयोगी समूहों के संभावित हमलों की चेतावनी दी है और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का संकल्प लिया है। उनकी बयानबाजी तेजी से उग्र हुईरू उन्होंने तेल अवीव पर परमाणु विस्फोट की एआई-निर्मित तस्वीर पोस्ट की और यदि मतदाता उन्हें ठुकराते हैं तो श्दूसरे होलोकॉस्ट्य के खतरे का जिक्र किया। नेतन्याहू और आईडीएफ प्रमुख एयाल जमीर के बीच तनाव की खबरों ने चिंता बढ़ाई। इजरायली मीडिया ने गुमनाम सूत्रों के हवाले से बताया कि कश्मीर ने एक अनिर्दिष्ट सैन्य कार्रवाई के लिए, जो ईरान से टकराव भड़का सकती है, अधिक विचार-विमर्श तथा लिखित कानूनी अनुमति मांगी। रिपोर्टों से यह साबित नहीं हुआ कि हमले का आदेश दिया गया या हमला निकट हैय नेतन्याहू ने इस बयान को बकवास कहकर खारिज किया। सैन्य प्रमुख के हवाले से यह भी कहा गया कि चुनाव से पहले ईरान पर हमले की कोई परिचालन जरूरत नहीं है। अगले दो दिनों में इजरायली हमले की संभावना को रिपोर्टों के आधार पर जिम्मेदारी से आंका नहीं जा सकता। समय स्पष्ट रूप से संवेदनशील हैरू हमला जवाबी कार्रवाई भड़का सकता है, मतदान बाधित कर सकता है या मौजूदा नेता के सुरक्षा कथानक को मजबूत कर सकता है, जबकि सोचा-समझा ठहराव तनाव का जोखिम घटा सकता है। जोखिम वास्तविक हैय निश्चितता नहीं। अमेरिकी रुख असामान्य रूप से दृश्यमान है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर नेतन्याहू का समर्थन किया और इजरायलियों से उन्हें वोट देने का आग्रह किया, जो निकटता दिखाता है पर चुनाव को अमेरिकी राजनीति से उलझा दिखाने का जोखिम भी रखता है साथ ही, व्हाइट हाउस अधिकारियों के नेतन्याहू की परमाणु-विस्फोट वाली पोस्ट से चिंतित होने की खबरें बताती हैं कि वाशिंगटन को केवल हर चुनावी चाल से तालमेल नहीं, बल्कि तनाव और गलतफहमी की भी चिंता है। अमेरिका शायद परिचित नेता के साथ निरंतरता पसंद करे, पर उसके पास एक और क्षेत्रीय संघर्ष में घिरने से बचने का कारण भी है। नेतन्याहू की जीत शायद ईरान के प्रति टकराव वाला रुख और फिलिस्तीनी राज्य पर मौजूदा कठोर रेखा कायम रखेगी। विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकार लहजा बदलकर और बसने वालों की हिंसा पर अधिक दृढ़ता से कार्रवाई कर वाशिंगटन, यूरोपीय देशों और अरब पड़ोसियों से इजरायल के संबंध सुधार सकती है पर विश्लेषक विदेश नीति में तेज पलटाव की संभावना सीमित देखते हैं, इजरायली आम सहमति ईरान पर सख्त और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की विरोधी बनी हुई है। व्यापक खतरा किसी एक चुनावी रात के फैसले से ज्यादा एक शृंखला-प्रतिक्रिया हैरू नाजुक गठबंधन, विवादित वैधता, ईरान संकट और गाजा में जारी तबाही। किसी भी गुट की जीत इजरायल के आंतरिक विभाजन नहीं सुलझाएगीय गतिरोध, गठबंधन वार्ता अटकने के दौरान, नेतन्याहू का मौजूदा कार्यकाल लंबा कर सकता है। चुनाव यह बदल सकता है कि शासन कौन करे। वह स्वयं उन संघर्षों को हल नहीं कर सकता जिन्होंने सुरक्षा को अभियान की प्रमुख भाषा बनाया, और जो मतों की गिनती के बाद भी क्षेत्र को आकार देते रहेंगे।

भागवत का ज्ञानेश पुराण!

राजेंद्र शर्मा

क्या संघ-भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए, देश की जनता के खिलाफ, भारतीय जनतंत्र के खिलाफ और संविधान के खिलाफ बाकायदा युद्घ छेड़ने का फैसला कर लिया है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की जनतंत्र को ही ध्वस्त करने वाली करतूतों के खिलाफ राजधानी दिल्ली समेत देश भर में पिछले करीब महीने भर में सामने आए जनता के विक्षोभ और एक ओर राजनीतिक विपक्ष तो दूसरी ओर युवाओं, मजदूरों, किसानों, मध्यवर्गीय पेशेवरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्घिजीवियों आदि के लगातार फैलते आंदोलन के सामने, मोदी-शाह की सरकार के साथ-साथ संघ-भाजपा जोड़ी के शीर्ष ने जो टकराव की मुद्रा अपनायी है, उससे उसके युद्घ के लिए सन्नद्घ होने का ही पता चलता है। यह संयोग ही नहीं है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, विजयदशमी के अपने परंपरागत संबोधन में एक तरह से इस युद्घ ऐलान किया है। इस ऐलान को यह तथ्य और भी अनिष्टसूचक अर्थ दे रहा था कि आरएसएस, विजयदशमी को अपना स्थापना दिवस मानता है और इस अवसर पर एक ओर अगर संघ प्रमुख का श्मार्गदर्शकश संबोधन होता है, तो दूसरी ओर शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है। इस बार का विजयदशमी आयोजन इसलिए और भी खास था कि इसके साथ, देश-विदेश में हुए आरएसएस के शताब्दी वर्ष आयोजनों का समापन हो रहा था। इस तरह, संघ के एक सौ एक वें वर्ष में प्रवेश के मौके को संघ प्रमुख ने इस युद्घ की घोषणा करने के लिए चुना है, इससे इस घोषणा की मारकता और बढ़ जाती है। संघ प्रमुख ने वोट चोरी से लेकर चुनाव की ही चोरी तक के असंख्य रहस्योद्घाटनों की ओर एक नजर तक डालना गवारा नहीं किया, जो गोदी मीडिया के जरिए मुख्यधारा के लगभग समूचे मीडिया की लंबी चुप्पी के बावजूद, देश में ही नहीं विदेश तक, भारतीय जनतंत्र पर वास्तविक चिंताएं पैदा कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने यह सुनने के बजाय अपने कान बंद ही कर लिए कि सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारी, श्वोट के अधिकार को बचाने की मांग कर रहे थे, जोकि जनतंत्र की बुनियादी इकाई है, वह ईट है जिससे जनतंत्र की इमारत खड़ी होती है और संघ प्रमुख की जुबान से इसकी सराहना का एक शब्द तक नहीं निकला कि तिरंगा ओढ़ कर सबसे बढ़कर युवा पीढ़ी ही आज जनतंत्र को बचाने की चिंता से संचालित होकर, सड़कों पर उतर रही है। जंतर मंतर-1 के फौरन बाद, भागवत ने संघ-भाजपा के राजनीतिक नुकसान को कम करने की सचेत कोशिश में, जेन जी को पटाने के लिए जो कुछ अच्छी-अच्छी बातें कही थीं, उनसे भ्रमित हुए सहज-विश्वासी लोगों को जरूर, जंतर मंतर-1 और जंतर मंतर-2 के बीच, छः महीने से भी कम में भागवत की इस पल्टी पर हैरानी होगी। लेकिन, वास्तव में इसमें हैरानी की कोई बात है नहीं। छरू महीने पहले का भागवत का श्जेन जी प्रेम्य भी, देश की सत्ता पर संघ-भाजपा की पकड़ को मजबूती देने के लिए था और अब उसी सत्ता के दमनचक्र के लिए तर्क जुटाने के लिए भागवत जेन जी के हरकत में आने को श्भारतविरोधी ताकतों के षड्यंत्रश का हिस्सा बताने से नहीं हिचकते हैं। बिना नाम लिए किंतु स्पष्टसूचतः चुनाव की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जारी वर्तमान आंदोलन को देश के लिए ही खतरा बताते हुए संघ प्रमुख कहते हैं, परंतु जब... आंदोलन राजनीति का साधन बन जाता है, किसी व्यक्ति, समूह या विचार के प्रति विरोधी शत्रुभाव लेकर चलता है, तब इसका लाभ भारत को दबाना चाहने वाली शक्तियां लेती हैं। इससे पहले, संघ प्रमुख आंदोलनों के लिए इसका उपदेश तो करते ही हैं कि, परंतु आंदोलन समाधान देने के लिए होने चाहिएश और यह भी कि भावनाएं तीव्र होने पर भी हमारे संविधान कानून की मर्यादा में, बोलचाल चलन के भद्र व्यवहार के संकेतों की मर्यादा में हमारी कृतियां हों, यह ध्यान रखना चाहिए। वोट, सस्ती लोकप्रियता अथवा राजनीतिक लाभ का लोभ, हमारे विवेक और सद्भावना पर हावी न हो, यह चिंता करनी ही पड़ेगी। इससे आगे जाकर वह एक ओर तो वर्तमान संघ-भाजपा शासन को देश के सामने मौजूद समस्याओं के लिए जवाबदेही से बरी करते हुए कहते हैं कि, समाज की सब समस्याएं शासन ही सुलझा सकता है...ऐसा भी अनुभव नहीं है।श दूसरी ओर, आंदोलन मात्र की सार्थकता को ही नकारते हुए वह दावा करते हैं, आंदोलनों से ही समस्याएं सुलझती हैं, ऐसा भी अनुभव नहीं है।श भागवत क्या कहना चाहते हैंकृशासन समस्याएं सुलझाएगा नहीं, आंदोलन से समस्याएं सुलझेंगी नहींय लोगों को जो है उसे नियति मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना चाहिए। बेशक, संघ-भाजपा की सत्ता को बचाने के लिए जनता के लिए भागवत की यही सलाह है। लेकिन, भागवत संघ-भाजपा के राज के संदर्भ में देशवासियों को निष्क्रियता का संदेश देने तक ही नहीं रहते हैं। इससे आगे बढ़कर वह मौजूदा शासन के पक्ष में युद्घ का आह्वसूचन भी करते हैं। और ऐसा करते हैं, मौजूदा निजाम के तमाम विरोध को एक कल्पित श्भारत-विरोधी षड्यंत्र का हिस्सा बताने के जरिए।श पिछले दशकों में भारत ने स्वयं की शक्ति तथा सुनीति के कारण विश्व में धीरे-धीरे अपना स्थान बनाया है। भारत के समाज का पुरुषार्थ, सुदृढ़ नीतियां, नेतृत्व, देशाभिमान तथा विश्व के प्रति अपने दायित्व के बोध की जागृति के कारण सभी क्षेत्रों में यशस्वी हो रहा है। भारत की इस प्रकार की प्रगति के कारण विश्व के राष्ट्रों में अराजकता खड़ी कर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सहायक हो सकने वाले अपने पिट्ठूओं को वहां स्थापित करने का षड्यंत्र करने वाली ताकतों के खेल बंद होंगे। इस वस्तुस्थिति को ये आसुरी ताकतें जानती हैं। इसलिए, भारत ही उनका निर्णायक व सबसे बलवान प्रतिस्पर्द्धी और अंतिम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत, हिंदू व संघ को किस प्रकार तोड़ सकते (डिसमेंटलिंग) हैं, इसका विचार कर, योजना बनाकर वे कार्य करती हैं। उन्हीं की प्रकृति के कुछ लोग इसमें उन्हें सहायता के लिए मिल जाते हैं। क्षुद्र सत्ता स्वार्थ और विवेकहीनता के कारण कुछ महत्वाकांक्षी नेता लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन, संघ प्रमुख को भी इसका अंदाजा है कि यशस्वी भारतत्व के खिलाफ आसुरी ताकतों के हमले और भारत, हिंदू व संघ को डिसमेंटल करने की उनकी साजिशों की उनकी गप्प को शायद लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। शायद संघ के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले समझदार लोग तक उस पर विश्वास नहीं करें। इसलिए, वह फौरन इस खतरे को पश्चिम यूरोपीय देशों में हाल में देखने को मिले जन-असंतोष के उस उभार से जोड़ देते हैं, जिसे वर्तमान आंदोलन से मोदीशाही के बचाव के लिए, संघ परिवारी प्रचारतंत्र ने और उसके सहयोगी के तौर पर गोदी मीडिया ने, इसके दौरान हिंसा और आगजनी की यहां-वहां हुई कुछेक घटनाओं में ही घटाने की कोशिश की है। बेशक, संघ प्रमुख से फ्रांस, अल्बानिया आदि और अब इटली में भी उठी जन असंतोष की लहर के आर्थिक कारणों, खासतौर पर नव-उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट के प्रभावों को पहचानने की तो उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन, इसे बहाना बनाकर वह जो मानवता के लिए वैश्विक खतरे का आख्यान रचते हैं, उससे कुछ हैरानी तो होती ही है। समझदार लोग भी विचलित हों, ऐसा वातावरण है अथवा खड़ा किया जा रहा है। भारत सहित सारे विश्व में जो जो भद्रता, मांगल्य, सांस्कृति व मानवीय संस्कार है, वह सारा नष्टसूच-भ्रष्टसूच, उद्सूचध्वस्त करने की आसुरी प्रतिज्ञा लेकर पश्चिम से एक आंधी चली है। विश्व भर के तथाकथित प्रगत देश भी उससे त्रस्त, असहाय हैं। जाहिर है कि यह जेन जी हरकत में आने के बाद से संघ-भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा जिस तरह श्रीलंका, नेपाल तथा बांग्लादेश के घटनाक्रम के भारत में दुहराए जाने का डर दिखाया जाता रहा है और पिछले दिनों श्रिजीम चेंज्य के खतरे के बहाने जिसका शोर मचाया जाता रहा है, पश्चिम के संदर्भ से उसी की अपडेटिंग है। जैसी कि उम्मीद की जाती थी, भागवत के विदेशी षडयंत्र के खतरे के प्रचार का अनुमोदन करने के बाद से, भाजपा की ओर से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह ने, विपक्ष पर हमले की कमान संभाल ली है। लेकिन, विडंबना यह है कि संघ-भाजपा, किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र के आरोपों के जरिए, चुनाव की शुचिता की मांग के व्यापक आंदोलन को दबाने के जरिए, जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विश्वसनीय चुनाव का रास्ता रोककर, वैसी ही घटनाओं के दोहराए जाने का रास्ता बना रहे हैं, जैसी घटनाओं का डर दिखाकर वे ज्ञानेश कुमार और उसकी चुनावी धांधली की व्यवस्थाओं को बचाना चाहते हैं।

राशिफल

मेष :- कुछ अच्छे आसारों से मन प्रफुल्लित रहेगा। पेशे संबंधी कोई यात्रा में अवरोध संभव। शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभ के आसार बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।

बृषभ :- स्वयं पर भरोसा रख योजनाओं को सुचारू रुप से क्रियान्वित करें। सगे-संबंधों में सरल व व्यावहारिक बनने की कोशिश करें। अर्थाभाववश चिंता संभव।

मिथुन :- किसी महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध से मन हतोत्साहित होगा। संबंधों के प्रति कुछ नयी शिकायतें संभव। किसी विद्वान के विचारों से प्रभावित मन में उत्साह का संचार होगा।

कर्क :- कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा-प्रतियोगिता की दिशा में किया गया परिश्रम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव।

सिंह :- किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाताप संभव। रोजगार में अति व्यस्तता रहेगी किंतु कायरे को समय से पूर्ण करें।

कन्या :- समस्याओं के समाधान हेतु मन नयी-नयी युक्तियों पर केंद्रित होगा। महत्वपूर्ण कायरें के प्रति आलस्य न करें। छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित न हो। जीवन साथी से मधुरता कायम रखें।

तुला :- मन सकारात्मक विचारों से प्रभावित होगा। नाजुक संबंधों में संतुलित वाणी का प्रयोग करें। कोई हितैषी बिगड़े हुए संबंधों को सुधारवायेगा। रोजगार में अपनी क्षमता का लाभ उठाएंगे।

वृश्चिक :- सभी प्रकार के दायित्वों की पूर्ति हेतु संतुलित योजना पर चलें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सगे-संबंधियों का सहयोग प्राप्त होगा। विरोधियों की प्रबलता से कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयां संभव।

धनु :- नये समीकरण लाभकारी कार्य क्षमता के परिचायक होंगे। प्रणय संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आय-व्यय में संतुलन बनाने का प्रयत्न करें। महत्वपूर्ण कायरे में आलस्य का त्याग करें।

मकर :- कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा-प्रतियोगिता की दिशा में किया गया परिश्रम सार्थक होगा। रोजगार में प्रगति संभव।

कुंभ :- पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर उत्साहित होंगे। नियोजित कार्यकुशलता से प्रगति के लिए आशान्वित होंगे। सुखद कायरें की व्यस्तता रहेगी। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्क रहें।

मीन :- क्षमता से परे किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना हानिकार हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न करें। रोजगार में लाभ के नये अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में मेहमान के आगमन से व्यय संभव।

पराली की तपिश

यह विडंबना ही है कि जब देश की राजधानी में प्रदूषण की गंभीरता दिखायी देती है तो देश के नीति-नियंता पराली निस्तारण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं। अभी कोई अंतिम वैज्ञानिक अध्ययन भी सामने नहीं आया है कि पंजाब या अन्य राज्यों में पराली जलाने की प्रदूषण में कितनी फीसदी भूमिका है। लेकिन एक बात तो तय है कि पराली निस्तारण के जो भी विकल्प दिए जाते हैं, वे समय के अनुरूप किसान की सुविधा व आर्थिकी के अनुरूप नहीं हैं। यदि ये उपाय कारगर होते तो पराली प्रबंधन पर खर्च किए जाने वाले हजारों करोड़ रुपयों पर एक छोटी-सी माचिस भारी न पड़ती। किसान अपने खेतों में पराली को बार-बार यदि आग के हवाले करते हैं तो उसके पीछे का कड़वा सच यह भी है कि धान के अवशेषों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की तुलना में, पराली जला देना उसे सुविधाजनक, सस्ता तात्कालिक निस्तारण का विकल्प नजर आता है। निस्संदेह, जब तक आर्थिक रूप से लाभप्रद विकल्प किसान को नहीं दिया जाता, तब तक केवल सब्सिडी देने या दंडात्मक कार्रवाई करने के बहुत सीमित परिणाम ही सामने आएंगे। सूत्रों के अनुसार पंजाब में 15 सितंबर से 24 अक्तूबर के बीच खेतों में पराली जलाने की 574 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यदि पिछले साल के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो इसी अवधि में 561 घटनाएं ही सामने आई थीं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 270 घटनाएं अकेले तरनतारन में और 144 घटनाएं अमृतसर के इलाके में सामने आई हैं। जो बताती हैं कि इन दोनों इलाकों में विशेष रूप से ध्यान देने और पराली जलाने से रोकने के लिये ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में अभी भी धान की फसल काटने का मौसम चल रहा है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस साल पराली प्रबंधन के लिये 576 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा सब्सिडी वाली लगभग 21,155 मशीनें उपलब्ध कराई गई थीं। दरअसल, सरकारी आर्थिक मदद के बावजूद किसानों को मशीनों को चलाने के खर्च, धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बहुत कम समय समय मिलने और जरूरत के समय मशीनें न मिल पाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक तरीके से पराली प्रबंधन करने में प्रति एकड़ दो हजार से लेकर ढाई हजार रुपये तक खर्च आ सकता है। तभी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों को पराली जलाना सबसे आसान विकल्प लगता है। हालांकि, शासन व प्रशासन ने पराली जलाने से रोकने के लिये सख्ती बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार अब तक पराली जलाने के मामले में 113 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड में 205 रेड एंट्री की गई हैं। साथ ही 11.4 लाख रुपये का पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आर्थिक दंड लगाया गया है। निस्संदेह, देश में व्याप्त पर

एक ही घर से उठीं तीन अर्थियां, मृतक की बेटी की सरकारी नौकरी और एक-एक करोड़ रुपए देने की रखी मांग

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ का सआदतगंज इलाका इस वक्त सिर्फ चीखों, आंसुओं और गुस्से का गवाह बना हुआ है। सआदतगंज के ब्राह्मण टोला में जब एक ही घर से तीन–तीन अर्थियां उठीं, तो वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा कांप गया। पुलिस की ढिलाई, दबंगों की गुंडागर्दी और एक हंसते–खेलते परिवार के तबाह होने की यह वो खूनी कहानी है जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। जिस घर में महज कुछ दिनों बाद यानी 5 दिसंबर को बेटे सुयश के सिर पर सेहरा सजने वाला था और शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां आज मातम का पहाड़ टूट पड़ा है। सोमवार को हुई इस खूनी वारदात में शिवाजी तिवारी, उनके छोटे भाई शिवेंद्र उर्फ शंभू तिवारी और बेटे सुयश की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद जब तीनों के शव एक साथ घर पहुंचे, तो परिजनों की चीख–पुकार से पूरा मोहल्ला दहल उठा। गुलाला घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले घर के बाहर रखीं तीन अर्थियों ने हर देखने वाले की आंखें नम कर दीं। मृतक शिवेंद्र तिवारी की पत्नी रुचि तिवारी बताया कि सोमवार सुबह करीब 10रू35 बजे शुरू हुआ। शिवेंद्र जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, तभी आरोपी राजेश शुक्ला, ऋषभ शुक्ला, गिरीश शुक्ला, दिनेश शुक्ला, मुन्ना बाबू और अन्य लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आरोपियों ने पहले तो गाली–गलौज की और फिर लाठी–डंडों व पत्थरों से हमला बोल दिया। चीख–पुकार सुनकर जब शिवाजी तिवारी और उनका बेटा सुयश बीच–बचाव करने पहुंचे, तो दबंगों ने उन्हें भी दबोच लिया। तीनों की बेदर्दी से पिटाई करने के बाद आरोपियों ने उन्हें गोली मार दी और एक ही पल में परिवार के तीन चिराग बुझा दिए। हत्याकांड की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। देखते ही



देखते मौके पर करीब 1500 लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को फांसी देने, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने व एनकाउंटर करने की मांग रखी। भीड़ का गुस्सा इस कदर था कि पूरे इलाके में भारी तनाव बन गया। इस तिहरे हत्याकांड ने लखनऊ पुलिस की चौकसी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक शिवाजी तिवारी की बहन रेखा ने सीधे तौर पर पुलिस से पूछा कि जब आरोपी राजेश शुक्ला को जिला बदर घोषित किए जाने की बात कही जा रही थी, तो वह खुलेआम थाने में और इलाके में कैसे घूम रहा था? उन्होंने मांग की कि जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को भी जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। लोगों के भारी विरोध और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया और लापरवाही के आरोप में चौकी प्रभारी अजय कुमार चौरसिया तथा इंस्पेक्टर संतोष आर्या को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। मृतक शिवेंद्र तिवारी की बेटी सुमेधा तिवारी ने बताया कि इस वारदात से दो घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा, ष्मेरी मांग है कि प्रताड़ित दोनों परिवारों को योगी सरकार की तरफ से 1–1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाए। इसके साथ ही, मेरे पिता स्व. शिवेंद्र तिवारी की पत्नी (मेरी मां) को जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कंपनियों के मर्जर–डीमर्जर पर स्टांप शुल्क के नियम बदलेंगे, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कंपनियों के विलय (मर्जर) और विभाजन (डी–मर्जर) की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए योगी सरकार ने कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कंपनियों के विलय और विभाजन से संबंधित नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत कंपनियां निर्धारित स्टांप शुल्क देकर स्टांप एवं पंजीयन विभाग में पंजीकरण करा सकेंगी। हालांकि, व्यवस्था लागू होने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने बताया कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश में इसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण उद्यमियों को कंपनियों के विलय और विभाजन के पंजीकरण में परेशानी होती थी। रविंद्र जायसवाल के मुताबिक, यदि कोई कंपनी दो या चार हिस्सों में विभाजित होती है अथवा कई कंपनियों का एक कंपनी में विलय होता है, तो शेयर मूल्य पर 0.5 फीसदी स्टांप शुल्क देकर स्टांप एवं पंजीयन विभाग में पंजीकरण कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कंपनी के पास



संपत्ति होने की स्थिति में स्टांप ड्यूटी की गणना के लिए दो प्रतिशत सर्किल रेट के बराबर शुल्क और 0.5 फीसदी की दर में से जो अधिक होगा, उसका भुगतान करना होगा। जायसवाल ने कहा कि अभी कंपनी का पंजीकरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास होता है, लेकिन विलय और विभाजन के बाद पंजीकरण के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। नई व्यवस्था से इस प्रक्रिया में सुविधा मिलने की उम्मीद है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यह विषय समवर्ती सूची में आता है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। प्रस्ताव को लागू करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। पहले इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और फिर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद ही नई व्यवस्था लागू हो सकेगी।

छोटे किसानों और उद्यमियों को योगी सरकार का तोहफा, राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी

पशुपालन से बढ़ेगी किसानों की आय

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने राज्य पशुधन मिशन एसएलएम को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य पशुधन अर्थव्यवस्था को संगठित कर आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और वैश्विक व्यापार से जोड़ना है। मिशन में विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों और उद्यमियों पर ध्यान दिया जाएगा।पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है और दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब उत्पादकता, बाजार व्यवस्था, मूल्य संवर्धन और डिजिटल प्रबंधन को मिशन के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों



की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में पहली बार राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी दी गई है। साहीवाल, देसी और हरियाणवी जैसी उन्नत नस्लों के विकास और नस्ल सुधार पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही एक उन्नत गाय के लिए 40 हजार रुपये और दो के लिए 80 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान है। बकरी, भेड़, शूकर और मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों को सौ–सौ चूजे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।पशुधन मंत्री ने बताया कि उद्यमिता को पांच उप–मिशन के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास, पशुधन एवं पोल्ट्री नस्ल विकास, नवाचार एवं डिजिटल लाइवस्टॉक, चारा एवं आहार विकास तथा अनुसंधान, वैश्वीकरण एवं ज्ञान प्रणाली विकास शामिल हैं। इनके माध्यम से लाइवस्टॉक स्टार्टअप्स, चारा उत्पादन, मूल्य संवर्धन, उत्पादक संगठनों और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। एआई, डिजिटल ट्रेसबिलिटी और जलवायु अनुकूल तकनीकों से पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता तथा बाजार पहुंच बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रशिक्षण से पशुपालकों का कौशल विकास भी किया जाएगा। यह राज्य वित्तपोषित योजना है। निर्धारित माइलस्टोन पूरे होने, स्क्रीनिंग समिति की प्रक्रिया और पीएसी की स्वीकृति के बाद चयनित परियोजनाओं का अनुदान सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगा। अवसंरचना निर्माण और सेवाओं के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

बीजेपी को बड़ा झटका, 2 बार के पूर्व सांसद ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की आंवला (बरेली) लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो बार सांसद रहे धर्मेंद्र कुमार कश्यप मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कश्यप ने लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से सपा की सदस्यता ली। कश्यप अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं। सूत्रों ने बताया कि कश्यप को राज्यसभा का टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। भाजपा ने बरेली जिले से ही पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री व झारखंड के पूर्व राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया, जो राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में



पत्रकारों को संबोधित करते हुए कश्यप ने कहा कि राज्य में खराब कानून–व्यवस्था के कारण लोग भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उनकी अपनी जाति के लोगों पर नहीं चलता, बल्कि गरीबों को निशाना बनाया जाता है। अखिलेश यादव ने कश्यप का सपा में स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद, सात अक्टूबर को कश्यप ने फेसबुक पर समुद्र किनारे सूर्यास्त की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिस पर टाटा बाय–बाय लिखा था। इसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में वापस लौटने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। कश्यप को रुहेलखंड (उत्तर–पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में कश्यप समुदाय के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक माना जाता है। वह मई 2013 में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वह 2014 तथा 2019 में लोकसभा में आंवला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आंवला सीट से बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

दीपोत्सव में दिखाई देती है श्री राम नगरी के पुनर्वैभव की सबसे मनोहारी अभिव्यक्ति

श्री हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप करने वाली सरकार को राम की अयोध्या के विकास से नहीं था मतलब–सीएम

संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पश्चात प्रारम्भ हुए दीपोत्सव को लेकर अपने भाव व उत्साह प्रदेशवासियों से साझा किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम अपने 10वें भव्य–दिव्य दीपोत्सव के स्वागत में पुलकित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव का वर्णन करते हुए लिखा कि लाखों दीपों की अलौकिक आभा से जगमगाते सरयू तट, रामायण के प्रसंगों को जीवंत करती मनोहारी झांकियां, भव्य शोभायात्राएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस महोत्सव में त्रेतायुग की स्मृतियों को फिर से जीवंत करेंगी। हर दीप प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक होगा और हर लौ हमारी सनातन संस्कृति के गौरव का उद्घोष करेगी। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर प्रहार किया, बताया– वर्ष 2017 से पहले प्रभु श्री राम की प्राणप्रिय नगरी अयोध्या जी उपेक्षा, अव्यवस्था और बदहाली का दंश झेल रही थीं। निर्दोष रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वाली और पवित्र श्री हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप करने वाली सरकार को श्राम की अयोध्याश के विकास से क्या मतलब?मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से वर्ष 2017 के बाद श्री अयोध्या जी में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया सूर्योदय हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से रामनगरी अपने प्राचीन वैभव को पुनः प्राप्त कर रही है। भव्य–दिव्य श्री राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुसज्जित रामपथ, नव्य घाट, आधुनिक सुविधाएं और सोलर सिटी के रूप में विकसित होती अयोध्या आज आस्था और आधुनिकता की अद्भुत संगम स्थली बन चुकी है।श्री राम नगरी के इस पुनर्वैभव की सबसे मनोहारी अभिव्यक्ति दीपोत्सव में दिखाई देती है। वर्ष 2017 में 1.71 लाख दीपों से प्रारंभ हुई दीपोत्सव की यात्रा आज देश–दुनिया के करोड़ों रामभक्तों की श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक बन चुकी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामभक्त दीप प्रज्ज्वलन का विश्व कीर्तिमान बनाने को तैयार हैं। यह दीपोत्सव उन पीढ़ियों के स्वप्नों का उजास है, जिन्होंने सदियों तक अपने राम की अयोध्या को त्रेतायुगीन स्वरूप में देखने की अभिलाषा संजोए रखी। आज इसका हर दीप तुष्टीकरण के अंधकार पर आस्था की विजय, सांस्कृतिक स्वाभिमान के उदय और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प बनकर प्रज्वलित हो रहा है।

पहले यूपी में माफिया राज था, अब युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर : योगी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में माफिया व अपराधियों को बढ़ावा दिया गया तथा सरकारी नौकरियों में योग्यता के बजाय सिफारिश और लेनदेन का बोलबाला था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति बदलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा आयोजित यूथ आइकन समिट में योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले पहचान और सुरक्षा का संकट था, जबकि उनकी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाकर स्थिति बदली है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा, हमारे विपक्ष के मित्र दुष्प्रचार करने में पारंगत हैं। उन्होंने साल की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को प्रदेश के सभी विभागों में सीधी भर्ती के जरिये नौकरी देने की व्यवस्था की है। उन्होंने दावा

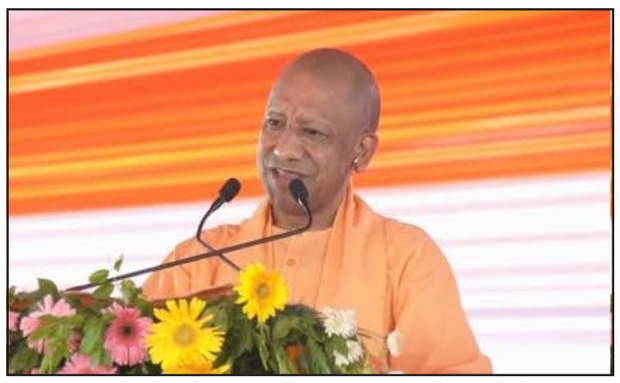

किया कि पहले प्रदेश में अपराधियों और माफिया का प्रभाव था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आदित्यनाथ ने कहा, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में श्एक जिला, एक माफियाश नहीं, बल्कि एक जिला, एक उत्पाद है। मुख्यमंत्री ने सरकारी सरकारों के दौरान नियुक्तियों में योग्यता के बजाय कथित तौर पर सिफारिश और लेनदेन को महत्व दिया जाता था। उन्होंने कहा कि एक बार उनके सामने ऐसी फाइल आई, जिसमें कुछ ऐसे लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाने का उल्लेख था जिन्होंने आवेदन तक नहीं किया था। आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पहले किसी भी नियुक्ति की योग्यता का आधार केवल सैफई सिंडिकेट से है, इस पर निर्भर करता था, उसकी योग्यता पर नहीं। उन्होंने कहा, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में हम लोगों ने साढ़े नौ लाख सरकारी नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं बिना किसी सिफारिश या लेनदेन के। इसमें कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आदित्यनाथ ने अगले छह महीने में एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि करीब 4500 उपनिरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले सप्ताह नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा 32 हजार से अधिक पुलिस कांस्टेबलों और 42 हजार होमगार्ड्स जवानों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र जल्द दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने खिलाड़ियों को भी श्पदक लाओ, पद पाओश की नीति के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 1,400 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 2017 के करीब 120 से बढ़कर अब 25,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 96 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां हैं, जिनसे 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार तीन गुना हुआ है और प्रति व्यक्ति आय में भी तीन गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। उनके मुताबिक, पहले 1.53 लाख ऐसे श्मजरेश (छोटी बस्ती) थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन उनकी सरकार ने वहां बुनियादी ढांचा विकसित किया। मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए।

ट्रिपल मर्डर कांड में बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी निलंबित, शव घर पहुंचते ही मची चीख-पुकार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज क्षेत्र में कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के तीन सदस्यों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सोमवार को हुई घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्य और कश्मीरी मोहल्ला चौकी प्रभारी अजय कुमार चौरसिया को निलंबित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, मारे गए लोगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के जिला सह–कार्यवाह शिवाजी तिवारी भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद भाजपा नेताओं और आरएसएस से जुड़े लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।



परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उसने बताया कि मामले के आरोपी ऋषभ शुक्ला (30) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और चार खोखे बरामद किए गए हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, सआदतगंज के नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में सोमवार को एक खाली भूखंड पर कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान हुई गोलीबारी में तिवारी परिवार के शिवाजी तिवारी, शिवेंद्र तिवारी (55) और सुयश तिवारी (30) की मौत हो गई। उसने बताया कि शिवेंद्र तिवारी की पत्नी रुचि तिवारी की शिकायत पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर पहुंचे भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव अभिजात मिश्रा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूरे थाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी थी। समय रहते कार्रवाई की गई होती, तो इस घटना को टाला जा सकता था। हम पूरे थाने के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है और इलाके में कानून–व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है।

अखिलेश यादव का निर्वाचन आयोग पर बड़ा हमला, बोले, चुनाव में हेरफेर की हो रही है बड़ी साजिश

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए चुनाव में हेरफेर की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों के खिलाफ हाल में की गई कार्रवाई से उनकी पार्टी की चिंताएं दूर नहीं होंगी। उन्होंने आगामी चुनावों के मद्देनजर लगातार सतर्क रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अब निर्वाचन आयोग जागा है और अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हमें इससे तसल्ली नहीं मिलेगी, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। क्या इन छोटी कार्रवाइयों के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं? वरना बाद में हम यही कहते रह जाएंगे कि देखिए, क्या हो गया। उन्होंने हालिया विधान परिषद चुनावों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया, षविधान परिषद चुनावों की मतगणना के दौरान मतपेटियों के अंदर बिना मुड़े हुए मतपत्र कैसे मिल सकते हैं? क्या किसी ने सोचा भी होगा कि मतपेटियों के अंदर खुले हुए, बिना मुड़े हुए मतपत्र मिलेंगे? ऐसा किसने किया होगा? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन या चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना ऐसा होना मुमकिन नहीं है। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, षनिर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने जो देखा है, उससे लगता है कि उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सपा प्रमुख ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस दौरान पात्र मतदाताओं, खासकर सपा समर्थकों को निशाना बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि 2019 में मतदान करने वाले कई लोगों के नाम 2022 की सूची से गायब थे। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने सवाल किया कि सत्ताधारी दल किसे श्घुसपैठियाश मानता है? उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आते ही घुसपैठियों का मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है। भाजपा को साफ करना चाहिए कि घुसपैठिये कौन हैं? चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि अगर चीन भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, तो क्या उन्हें घुसपैठिया नहीं कहा जाएगा? अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची संशोधन का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों के नाम हटाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा, हम भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन हमें उन प्रीपेड पार्टियों और नेताओं से भी सावधान रहना होगा, जिन्हें ओटीपी (निर्देश) कहीं और से मिलते हैं। अंत में, उन्होंने मांग रखी कि फर्जीवाड़े और असली मतदाताओं के नाम हटने से रोकने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए और मतदान प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जाए।

मईल में ब्लॉक स्तरीय बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न, बच्चों ने दिखाया दमखम

स्वाभिमान जागरण, मईल देवरिया

मईल, देवरिया। बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कंपोजिट विद्यालय बढ़ौना के खेल मैदान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत मशाल जुलूस एवं ध्वजारोहण के साथ हुई। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि काली प्रसाद ने कहा कि खेल हमारे समाज का आवश्यक अंग है। सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर दे रही है। बेसिक शिक्षा विभाग का यह प्रयास सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप सिंह ने कहा कि खेल जीवन का आवश्यक मंत्र है। विशिष्ट अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यह प्रतियोगिता नौनिहालों की प्रतिभा को संवारने का प्रेरणादायक और प्रभावी मंच है। यहां के बच्चे प्रदेश स्तर तक अपनी प्रतिभा



का लोहा मनवा सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान बच्चे हैं। क्रीड़ा परिणाम इस प्रकार रहे – कबड्डी प्राथमिक संवर्ग में गहिला की टीम विजेता तथा अकुबा की टीम उपविजेता रही। प्राथमिक बालक वर्ग दौड़ –

200 मीटर में प्रथम अरशद गहिला, द्वितीय अंकित बलिया उत्तर

100 मीटर में प्रथम किशन बढ़ौना, द्वितीय फिरोज बढ़ौना

50 मीटर में प्रथम अर्जुन अंडिला, द्वितीय नवाब अली

उच्च प्राथमिक बालक वर्ग –

100 मीटर में प्रथम आकाश चौहान पड़री गुराव, द्वितीय अतुल बलिया उत्तर

200 मीटर में प्रथम विकास यादव बढ़ौना, द्वितीय आकाश चौहान पड़री गुराव

बालिका वर्ग –

50 मीटर में प्रथम खुशी बढ़ौना, द्वितीय अनुष्का अकुबा

200 मीटर में प्रथम अनुष्का अकुबा, द्वितीय साधना बढ़ौना

400 मीटर में प्रथम साधना बढ़ौना, द्वितीय सोनम बढ़ौना, तृतीय करिश्मा मईल

कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सत्य प्रकाश कुशवाहा ने सभी अतिथियों को बुके, शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन धीरज कुमार मिश्रा, रूप कुमार, विंध्यवास और आशुतोष गुप्ता ने किया। इस अवसर पर राजकुमार, राम अनुज, आनंद यादव, धर्मेंद्र तिवारी, अरुण तिवारी, सुशील कुमार सिंह, भगवान यादव, संजय पांडे, अजय मणि, राम निरंजन, परमात्मा कुमार सिंह, राजेश यादव, व्यास यादव, बलवंत सिंह, शैलेश, धर्मेंद्र सिंह, संपूर्णानंद पांडे, रंजीत यादव, कमलेश, गौरव आनंद, आलोक भारती, फैसल जावेद, नागेंद्र मोहन नीरज, हरिओम पांडे, राजीव, ममता, संगीता, वंदना मौर्य उपस्थित रहे।

आईटीआई में प्रवेश के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

स्वाभिमान जागरण संवाददाता

देवरिया

प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) देवरिया केके राम ने बताया कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रवेश सत्र 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं रिक्त सीटों के सापेक्ष व्यवसाय और संस्थान के चयन की प्रक्रिया के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in पर नया आवेदन भरने के साथ ही पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी रिक्त सीटों के सापेक्ष अपनी पसंद के व्यवसाय एवं संस्थान का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। उन्होंने बताया कि आवेदन शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये तथा सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित है।

पति के दीर्घायु ,दाम्पत्य सुख का पवित्र पर्व है करवा चौथ - आचार्य अजय शुक्ल

करवा चौथ व्रत 29 को मनाया जाएगा

स्वाभिमान जागरण संवाददाता

सलेमपुर। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए आस्था, श्रद्धा और दांपत्य प्रेम का पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख–समृद्धि की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। आचार्य अजय शुक्ल ने बताया कि करवा चौथ व्रत 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि की शुरूआत सुबह 1 बजकर 6 मिनट पर होगा तथा समापन रात्रि 10 बजकर 9 मिनट पर होगा।चंद्रोदय रात्रि 8 बजकर 15 मिनट से 8 बजकर 33 मिनट पर जगह के अनुसार होगा। व्रत रखने वाली महिलाएं प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव तथा करवा माता का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। परंपरा के अनुसार सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू किया जाता है। शाम को पूजा स्थल की साफ–सफाई कर चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित किया जाता है। पूजा में रोली, अक्षत, पुष्प, धूप–दीप, फल, मिठाई, सुहाग सामग्री और जल से भरा करवा रखा जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर विघ्नों के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता का पूजन कर अखंड सौभाग्य एवं पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। पूजा के बाद करवा चौथ की कथा का श्रवण किया जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं परंपरा के अनुसार करवा का आदान–प्रदान भी करती हैं। चंद्रोदय के बाद महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं और उन्हें अर्घ्य अर्पित करती हैं। इसके बाद पति का दर्शन कर उनके हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर में 950 पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की गईं



स्वाभिमान जागरण संवाददाता कौशांबी

पशुपालन विभाग, जनपद कौशाम्बी के तत्वावधान में दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को विकासखंड मूरतगंज की न्याय पंचायत काजू के ग्राम पकसराई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय पशु आरोग्य शिविर/मेले का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम प्रधान की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर पशु चिकित्सा अधिकारी, सराय अकिल ने भी प्रतिभाग किया।

शिविर में क्षेत्र के पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के माध्यम से कुल 950 पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की गईं, जिनमें 650 बकरियाँ तथा 300 गाय एवं भैंस शामिल रहीं।

शिविर में पशुपालन विभाग की टीम द्वारा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक दवाओं का वितरण, आवश्यकतानुसार शल्य चिकित्सा तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रसित पशुओं का उपचार किया गया। पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच कर आवश्यकतानुसार दवाएँ एवं चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त पशुपालकों को पशुओं के नियमित टीकाकरण, समय–समय पर कृमिनाशन, संतुलित आहार, स्वच्छ पशुशाला तथा बेहतर प्रजनन प्रबंधन के संबंध में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि समय से कृत्रिम गर्भाधान कराने, रोगों की पहचान करने तथा बीमार पशुओं का समय पर उपचार कराने से पशुधन की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है।

शिविर के माध्यम से पशुपालकों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक पशुपालन पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाने के' लिए 31 दिसंबर तक' चलेगा विशेष संतृप्तिकरण अभियान

स्वाभिमान जागरण संवाददाता

चित्रकूट। जनपद में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष संतृप्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में शिविर लगाकर पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक प्रभात कुमार मेहता ने बताया कि अभियान के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में पात्र लोगों का नामांकन किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत नए बैंक खाते खोले जाएंगे और निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आधार सीडिंग, पुनः केवाईसी, लंबित सी–केवाईसी तथा बैंक खातों में नामांकन संबंधी विवरण को अपडेट करने का कार्य भी किया जाएगा। शिविरों के माध्यम से लोगों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय अभियान का समन्वय करेगा। इसमें संबंधित बैंक शाखाओं, ग्रामीण बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बैंक मित्रों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। अभियान की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। एलडीएम ने बैंक अधिकारियों और आमजन से अपील की है कि वे अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

आगरा में जाम के ये हैं प्रमुख कारण, जिनसे कराह रही ताजनगरी

संवाददाता

आगरा। जाम शहर की प्रमुख समस्या बन गया है। जिस रास्ते पर लोग निकलते हैं, वहीं उनके वाहन फंस जाते हैं। कहीं अवैध पार्किंग परेशान कर रही है तो कहीं अतिक्रमण की समस्या है। आम रास्ते ही नहीं बाजार में भी यह समस्या विकराल है। आरोप है कि विभागीय अधिकारी सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। जाम लगने पर खानापूर्ति के लिए पुलिसकर्मी आते हैं मगर समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है। भगवान टॉकीज, रामबाग, बिजलीघर, सिकंदरा, आईएसबीटी पर अवैध पार्किंग बड़ी समस्या है। एक तरफ ऑटो–ई रिक्शा खड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बसों की लाइन लगती है। ऐसे में हाईवे पर वाहन रुकते हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती के बाद भी इन वाहनों की पार्किंग पर रोक नहीं है। पुलिसकर्मी एक दिन कार्रवाई करते हैं, वाहनों को सीज किया जाता है। अतिक्रमण भी हटाया जाता है। अगले ही दिन पुलिस की कार्रवाई ढीली पड़ते ही फिर से वही स्थिति हो जाती है। माईथान निवासी दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि त्योहारी



सीजन शुरू होते ही शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बाजारों में बेतरतीब पार्किंग के कारण 5 मिनट का सफर तय करने में लोगों का 1 घंटा बर्बाद हो रहा है। शाहगंज, लोहामंडी और कोतवाली जैसे प्रमुख बाजारों में बढ़ता अतिक्रमण और अवैध पार्किंग समस्या की प्रमुख वजह है। जयपुर हाउस की नीनू गर्ग ने कहा कि वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं। सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण और जगह–जगह बने गड्ढे शहर में लगने वाले भीषण जाम का मुख्य कारण हैं। शाहगंज निवासी शिल्पी अग्रवाल ने कहा कि जाम की स्थिति इतनी विकट है कि घर से निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। उस पर स्मार्ट सिटी और मेट्रो निर्माण के अधूरे कार्यों ने शहरवासियों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ममता किरण का कहना है कि मरीज के लिए समय पर डॉक्टर का परामर्श मिलना बेहद जरूरी होता है। कभी–कभी घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। सेवला जाट की रहने वाली सुधा त्यागी ने बताया कि सड़कों पर बिना सोचे–समझे गाड़ियां खड़ी करने से जाम की स्थिति पैदा होती है। इससे न केवल शोर और प्रदूषण बढ़ता है बल्कि वाहन चालकों में आपसी विवाद भी होते हैं, इससे समस्या और गंभीर हो जाती है। कमला नगर निवासी सोनी मिश्रा ने बताया कि घर से निकलने से पहले यह पता करना पड़ता है कि किस रास्ते पर जाम नहीं होगा। सड़कों की बेतरतीब खुदाई से कई रास्ते पर रोजाना जाम में फंसना पड़ता है। इस तरफ पुलिस और संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है।

किसान, कांग्रेस की इंदिरा गांधी के शहादत दिवस से पहले पार्क तैयार कराने की मांग

एजेंसी

बांदा। जिले में खाद की किल्लत, इंदिरा पार्क की अधूरी व्यवस्था और गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने किसानों की परेशानी दूर करने, पार्क का काम पूरा कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने ज्ञापन में कहा कि जिलेभर में खाद की समस्या बनी हुई है। किसानों को खाद लेने के लिए सुबह से शाम तक कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। इसके बावजूद कई किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस ने प्रशासन से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शहादत दिवस है, लेकिन इंदिरा पार्क का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। पार्क में सफाई भी नहीं कराई गई है। कांग्रेस ने पार्क के बगल में कूड़ाघर की जगह पैरामाउंट वालों को आवंटित किए जाने के मामले की जांच कराने की मांग की। साथ ही शहादत दिवस से पहले पार्क का काम पूरा कराकर उसे खोलने की अपील की। कांग्रेस



ने बड़ोखर खुर्द ब्लॉक की ग्राम पंचायत गन्छा के कैता पुरवा और परहन पुरवा में घर–घर जल योजना की स्थिति पर सवाल उठाए। ज्ञापन के अनुसार, कैता पुरवा में पानी की टंकी बन चुकी है और पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन घरों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कैता पुरवा में स्कूल नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस के मुताबिक, गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए बजरंग पुरवा जाना पड़ता है। इसके अलावा गांव में स्वास्थ्य केंद्र और बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत पोल की व्यवस्था नहीं होने की समस्या बताई गई। कांग्रेस ने जिलाधिकारी से सभी समस्याओं की जांच कराकर जल्द समाधान सुनिश्चित करने की मांग की।

सुबह तक जिस मार्ग से गुजरना था मुश्किल, रात में ही बन गई सीसी सड़क

संवाददाता

आगरा। आगरा के धूलियागंज स्थित नमक की चक्की, जैन मंदिर पाय चौकी रोड पर रातोंरात सीसी सड़क का निर्माण करा दिया गया। धनकोट फव्वारा की पार्षद आरती शर्मा ने निर्माण में भारी अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानी सड़क खोदे बिना ही निर्माण किया गया और सभी सीवर चौंबर के ढक्कन इसके अंदर दबा दिए गए। इससे सीवर लाइन की सफाई मुश्किल हो जाएगी। पार्षद ने बताया कि रात 12 बजे तक निर्माण की सुगबुगाहट तक नहीं थी लेकिन सुबह 6 बजे सीसी से नई सड़क बनी मिली। निर्माण से पहले पुरानी सड़क की खुदाई, मलबा हटाने और जीएसबी डालनी चाहिए थी। किसी मानक का पालन नहीं किया गया।

इंजीनियर की पत्नी की लूटी चेन, फिर पिघलाकर बना दिया सोने का टुकड़ा; कानपुर के दो लुटेरे गिरफ्तार

संवाददाता

आगरा। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में फरीदाबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ललित की पत्नी की चेन और मंगलसूत्र कानपुर के दो लुटेरों ने छीनी थी। थाना, सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 15.3 ग्राम पीली धातु का पिघला टुकड़ा, 40 हजार रुपये, घटना में प्रयुक्त बाइक, दो मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है। ईंट मंडी रोड पर 17 अक्तूबर को ललित एक होटल में रुके थे। वह दिल्ली बिजली विभाग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वह अपने मामा के बेटे की शादी में शामिल होने आए थे। दोपहर तीन बजे के करीब उनकी पत्नी अर्चना अपनी बच्ची के साथ पैदल बाजार जा रही थीं। श्याम वृंदावन अपार्टमेंट के पास बाइक सवार बदमाशों ने पेंडल सहित चेन और मंगलसूत्र लूट लिया था। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरी के



आधार पर 25 अक्तूबर को पथौली–बिचपुरी नहर के पास पेट्रोल पंप से आरोपियों को गिरफ्तार किया।उनकी पहचान कानपुर नगर के नौबस्ता निवासी अमित गुप्ता उर्फ प्रदीप कुमार गुप्ता और कानपुर देहात के अमरपुर निवासी विजय चौहान उर्फ अमन के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों बड़े शहरों में मौका देखकर लूट और छिनैती करते हैं। महिला से छीनी चेन को पिघला कर उसके टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा सराफा बाजार में 52 हजार रुपये में बेचा था। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि अमित गुप्ता पर आगरा, कानपुर नगर, कानपुर देहात और लखनऊ में कुल 44 मामले दर्ज हैं। इनमें लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं। वहीं, विजय चौहान पर कुल तीन मामले दर्ज हैं। दोनों को न्यायालय ने जेल भेजा है। आरोपी वारदात के बाद चेन, मंगलसूत्र आदि को खुद ही पिघला देते थे। इसके बाद सराफ बनकर उसे बेच देते थे। आरोपियों से एक छोटा गैस सिलिंडर, एक छोटी गैस गन, एक सिलेट (जॉन पेपर) भी बरामद हुए हैं।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का शिक्षकों को संदेश– अंकों के पीछे नहीं, बच्चों की समझ विकसित करने पर दें जोर

संवाददाता

आगरा। डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से शुरू हुई सम्मेलन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा। शिक्षा पर मंथन सिर्फ बड़े विश्वविद्यालयों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम वहां होने चाहिए, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जहां से शिक्षा के प्रति लोगों की सोच बदली जा सके। लखनऊ विश्वविद्यालय और डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में सम्मेलन होना था,लेकिन मैने आगरा डॉ भीमराव विश्वविद्यालय को चुना । अब कानपुर देहात जैसे क्षेत्र में भी शिक्षा को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल रटने वाली शिक्षा देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वे चीजों को समझें और सीखें। जब वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी थीं, तब बच्चों को अंकों की पहचान कराना और उनकी बुनियादी



समझ विकसित करना महत्वपूर्ण मानती थीं। शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा में अंक हासिल करना नहीं, बल्कि बच्चों को सीखने के योग्य बनाना होना चाहिए। राज्यपाल ने गुजरात में अपने कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब उन्होंने कक्षाओं में शिक्षकों की कमी देखी तो एक साथ 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराई। भर्ती में मेरिट को आधार बनाया गया। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में पारदर्शिता जरूरी है। किसी की सिफारिश या दबाव के बजाय योग्यता के आधार पर शिक्षक चुने जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण पर ध्यान दिया गया, जबकि अन्य शिक्षकों को अनावश्यक रूप से स्थानांतरित नहीं करने का निर्णय लिया। इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी नीति नहीं बदली। राज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन जरूरी यह है कि काम जनहित में हो। उन्होंने अपने कार्यकाल में ट्यूशन व्यवस्था पर नियंत्रण और नकल रोकने के लिए नियम लागू कराने के प्रयासों का भी जिक्र किया।

स्वाभिमान जागरण
हिन्दी दैनिक

स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं सम्पादक इम्तियाज़ अंसारी द्वारा सुपीरियर प्रिन्टर्स 245 माहम सिटी तिकोनिया पारा लखनऊ,(उ०प्र०)–11 से मुद्रित एवं मीडिया हाउस 20ए शिवाजीमार्ग हुसैनगंज लखनऊ उ0प्र0–01 से प्रकाशित।

संपादक
आलोक कुमार केसरवानी
प्रधान संपादक
इम्तियाज़ अंसारी
6392273876
Email-dainikswabhimanjagran.india@gmail.com

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं अस्थाई है समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ मान्य होगा।